जी.एन. वर्मा

बनाम

झारखंड राज्य और अन्य

(आपराधिक अपील संख्या 2004 का 122)

मार्च 6, 2014

[रंजना प्रकाश देसाई और मदन बी. लोकुर, न्यायमूर्ति]

खान-अधिनियम, 1952

1952 का अधिनियम का धारा 72 बी, आर एल डब्लू धारा 2 जे और 8(15) और कोयला खान विनियमों का विनियमन 8क-मानित अभिकर्ता-खदान में घातक दुर्घटना-शिकायत-मानित अभिकर्ता के रूप में शिकायत में निर्दिष्ट मुख्य महाप्रबंधक की देयता-आयोजितः केवल एक व्यक्ति जो मालिक की ओर से कार्य करने के लिए अधिकृत है या मालिक की ओर से कार्य करने का इरादा रखता है, उसे एजेंट माना जा सकता है --यदि कोई बयान नहीं दिया गया है या मालिक द्वारा कोई संकेत दिया गया है जो अपीलार्थी को अपनी ओर से कार्य करने या कार्य करने के लिए सक्षम बनाता है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि वह खदान के लिए एक मानित एजेंट था-धारा 2 (जे) जो 'खदान' को परिभाषित करती है, जिसमें खदान के संबंध में किसी भी प्रशासनिक कार्यों का कोई संदर्भ नहीं है, लेकिन केवल उससे संबंधित तकनीकी मामले हैं-प्रशासनिक कर्तव्यों का पालन करते समय अपीलार्थी को खान के तकनीकी मामलों में शामिल माना नहीं जा सकता है। --इसके अलावा, शिकायत में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि अपीलार्थी ने खदान के मालिक की ओर से कार्य किया या कार्य करने के लिए कथित रूप से कार्य किया या उसने किसी खदान के प्रबंधन, नियंत्रण, दृश्य या निर्देश में भाग लिया और इसलिए, उसके खिलाफ कार्यवाही के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया है - मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने शिकायत का संज्ञान लेने और अपीलार्थी को समन जारी करने में गलती की-अपीलार्थी के खिलाफ शिकायत को रद्द कर दिया जाता है।

अपीलार्थी के खिलाफ 30.08.2004 को इस आरोप पर आपराधिक शिकायत दर्ज की गई थी कि निषेधात्मक आदेश के बावजूद संबंधित कोयला खान में 09-03-2000 को या उसके आसपास कोयले का निष्कर्षण किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप एक घातक दुर्घटना हुई। निषेधात्मक आदेश के उल्लंघन का संकेत देने वाली जांच रिपोर्ट के परिणामस्वरूप, खान निरीक्षक ने मामला सं. 2000 की धारा 323 के अनुसार तीन अभियुक्तों, अर्थात् अपीलार्थी, जो मुख्य महाप्रबंधक था और जिसे संबंधित कोयला खान के अभिकर्ता के रूप में वर्णित किया गया था, कोयला खान के अभिकर्ता और कोयला खान के प्रबंधक के खिलाफ केस दायर किया कि उन्होंने खान अधिनियम, 1952 की धारा 72-बी के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने शिकायत का संज्ञान लिया और अपीलार्थी सहित अभियुक्त को समन जारी किया। अपीलार्थी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के तहत एक याचिका दायर की गई जिसमें कार्यवाही और उसे जारी किए गए समन को रद्द करने की मांग की गई। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने मामले को खंड पीठ को भेजा, जिसने यह अभिनिर्धारित किया कि अधिनियम की धारा 18 (5) के साथ पठित अभिकर्ता की विस्तारित परिभाषा को देखते हुए, खदान के मुख्य महाप्रबंधक को किसी खदान या उसके किसी हिस्से के प्रबंधन, नियंत्रण, पर्यवेक्षण या निर्देश के लिए जिम्मेदार अभिकर्ता माना जाएगा और याचिका को खारिज कर दिया।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

कहाः 1 यह न्यायालय लगातार इस विचार को अपना रहा है कि जब कोई क़ानून अपराध पैदा करता है और जुर्माने और कारावास का जुर्माना लगाता है, तो धारा के शब्दों का सख्ती से अर्थ विषय के पक्ष में लगाया जाना चाहिए। [पैरा 24] [635-जी; 636-ए]|

डब्ल्यू.एच. किंग बनाम भारत गणराज्य **(1952) एस.सी.आर. 418 पर निर्धारित**

1. 2 यह सच है कि खान अधिनियम, 1952 में "अभिकर्ता" का एक विस्तारित अर्थ है। यह न केवल एक ऐसे व्यक्ति को अपने दायरे में लाता है जिसे खदान के संबंध में एक एजेंट के रूप में नियुक्त किया जाता है, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति को भी लाता है जिसे एजेंट के रूप में नियुक्त नहीं किया जाता है, बल्कि जो खदान के मालिक की ओर से कार्य करता है या कार्य करने का इरादा रखता है और खदान या उसके किसी भी हिस्से के प्रबंधन, नियंत्रण, पर्यवेक्षण या दिशा में भाग लेता है। [पैरा 17] [633-सी-डी]

1. 3 कोयला खान विनियमों के विनियम 8-ए में खदान के मालिक को खदान के प्रबंधन, नियंत्रण, पर्यवेक्षण या निर्देश के संबंध में मालिक की ओर से कार्य करने के लिए अधिकृत प्रत्येक व्यक्ति का नाम और पदनाम लिखित रूप में प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। अभिलेख पर यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि ऐसा कोई बयान खदान के मालिक द्वारा मुख्य निरीक्षक या अधिनियम के तहत नियुक्त क्षेत्रीय निरीक्षक को दिया गया था। केवल एक व्यक्ति जो मालिक की ओर से कार्य करने के लिए अधिकृत है या मालिक की ओर से कार्य करने का इरादा रखता है, उसे एजेंट माना जा सकता है। यदि कोई बयान नहीं दिया गया है या मालिक द्वारा कोई संकेत दिया गया है जो अपीलार्थी को अपनी ओर से कार्य करने या कार्य करने के लिए सक्षम बनाता है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि वह खदान के लिए एक मानित एजेंट था। [पैरा 22] [635-बी-ई]

1.4 'खान' शब्द को 'खान अधिनियम, 1952' की धारा 2यू में परिभाषित किया गया है और इसमें खदान के संबंध में किसी भी प्रशासनिक कार्य का कोई संदर्भ नहीं है, बल्कि केवल उससे संबंधित तकनीकी मामले हैं। अपीलार्थी संबंधित कोयला खदान का मुख्य महाप्रबंधक था और यह मान लेना संभव नहीं है कि प्रशासनिक कर्तव्यों का पालन करने के अलावा, वह खदान से संबंधित तकनीकी मामलों में भी शामिल था। [पैरा 23] [635-ई-एफ]

1. 5 इसके अलावा, शिकायत में कहीं भी यह आरोप नहीं लगाया गया है कि अपीलार्थी ने खदान के मालिक की ओर से कार्य किया या कथित रूप से कार्य किया या उसने किसी खदान के प्रबंधन, नियंत्रण, पर्यवेक्षण या निर्देशन में भाग लिया। शिकायत में कथन नीरस और अस्पष्ट है। शिकायत में अपीलार्थी के खिलाफ कोई आरोप नहीं है। उनके बारे में एकमात्र कथन यह है कि वे खदान के मुख्य महाप्रबंधक/मानित अभिकर्ता थे और खदान के पर्यवेक्षण, प्रबंधन और नियंत्रण का प्रयोग कर रहे थे और उस क्षमता में यह देखने के लिए बाध्य थे कि सभी खनन कार्य अधिनियम, नियमों, विनियमों, आदेशों के अनुसार किए गए थे। मामले के तथ्यों पर और अपीलार्थी के खिलाफ दायर शिकायत में किसी भी आरोप के अभाव को देखते हुए, उसके खिलाफ कार्यवाही के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया है। इन परिस्थितियों में, अपीलार्थी के खिलाफ अधिनियम की धारा 72-बी के तहत कार्यवाही करने का कोई आधार नहीं है। इसलिए, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने शिकायत का संज्ञान लेने और अपीलार्थी को समन जारी करने में गलती की। उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है और अपीलार्थी के खिलाफ शिकायत को खारिज कर दिया जाता है।[पैरा 18,20,25 और 26] [633-ई, जी, 634-एफ-जी; 636-बी-सी]

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड बनाम हरमीत सिंह पेंटल और अन्य **2010 (2) एससीआर 805 = (2010) 3 एससीसी 330-पर निर्भर|**

आर. जे. सिन्हा बनाम राज्य **1983 बी. एल. टी. (प्रतिनिधि) 97-उद्धृत।**

केस लॉ सन्दर्भ

1983 बी. एल. टी. (रेप.) 97 उद्धृत पैरा 11
2010 (2) एस. सी. आर. 805 पैरा 19 पर निर्भर
(1952) एस. सी. आर. 418 पैरा 24 पर निर्भर

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकार : आपराधिक अपील संख्या 2004 की 122|

रांची में झारखंड उच्च न्यायालय के दिनांक 19.09.2002 के निर्णय और आदेश से क्रिमिनल विविध संख्या 2000 का 8331(आर)|

एस. बी. उपाध्याय, परम कुमार मिश्रा, कौस्तुव पी. पाठक, संतोष मिश्रा, रामेश्वर प्रसाद गोयल अपीलार्थी की ओर से।

सिद्धार्थ लूथरा, ए. एस. जी., अरिता सिंघला, सी. मंगल शर्मा, एच.डी.एस. मेहरा, एम. पी. एस. तोमर, रवींद्र कुमार वर्मा, जयेश गौरव, गोपाल प्रसाद उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय द्वारा दिया गया था:

मदन बी. लोकुर, न्यायधीश. 1. कानून के प्रश्नों के अलावा, यह अपील प्रक्रिया री-इंजीनियरिंग और मामले के प्रबंधन का एक गंभीर मुद्दा उठाती है, एक ऐसी चिंता जिसे हमें संबोधित करने की आवश्यकता है|

2. अपीलार्थी जी. एन. वर्मा के खिलाफ 30 अगस्त 2000 को आपराधिक शिकायत दर्ज की गई थी। उन्होंने शिकायत को रद्द करने की मांग की जिसे उच्च न्यायालय ने 19 सितंबर 2002 को खारिज कर दिया। उक्त आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए इस न्यायालय द्वारा 27 जनवरी 2004 को विशेष अनुमति दी गई थी।

3. इस तथ्य के बावजूद कि इस न्यायालय ने विचारण न्यायाधीश के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगाने का कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया, हमें सूचित किया गया कि आपराधिक शिकायत ने पिछले तेरह वर्षों में कोई प्रगति नहीं की है। हम इस स्थिति से स्पष्ट रूप से परेशान थे।हालाँकि, हमें बाद में सूचित किया गया कि मुकदमा आगे नहीं बढ़ सका क्योंकि मामले के मूल रिकॉर्ड इस अदालत को भेज दिए गए थे। मूल अभिलेखों के अभाव में, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट स्पष्ट रूप से मुकदमे को आगे नहीं बढ़ा सके।

4. यह समय उन नियमों, प्रथाओं और प्रक्रियाओं पर गौर करने और उन पर पुनर्विचार करने का है जिनका न केवल इस न्यायालय द्वारा बल्कि अन्य उच्च न्यायालयों द्वारा भी पालन किया जा रहा है, जिसमें बिना किसी स्पष्ट कारण के मुकदमे के मूल रिकॉर्ड को नियमित रूप से बुलाने की आवश्यकता होती है, सिवाय इसके कि नियम, प्रथाएं और प्रक्रियाएं उनकी मांग के लिए प्रदान करती हैं। यह दिनचर्या मुकदमे को पूरी तरह से रोक देती है और पीड़ित वादी को न्याय देने में देरी करती है।यह समय मुकदमे के मूल अभिलेखों के प्रथागत समन पर निर्णय लेने का है, विशेष रूप से कार्यवाही के अंतर्वर्ती चरण में।

यह अपील इस बात का संकेत है कि कुछ मामलों के निपटारे में केवल इसलिए देरी होती है क्योंकि हम कुछ पुराने नियमों, प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन करते हैं।यदि मूल अभिलेखों को नियमित रूप से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से नहीं बुलाया गया होता, तो हमें विश्वास है कि मुकदमा किसी न किसी तरह से कई साल पहले समाप्त हो सकता था और न्याय का शीघ्र वितरण एक मृगतृष्णा में परिवर्तित नहीं होता|

6. विचार के लिए प्रमुख प्रश्न यह है कि क्या अपीलार्थी जी. एन. वर्मा के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की गई आपराधिक शिकायत का संज्ञान शिकायत में उनके खिलाफ लगाए गए किसी भी आरोप के अभाव में खारिज किए जाने का हकदार है।एक संबंधित प्रश्न यह है कि क्या अपीलार्थी जी. एन. वर्मा को करकट कोलियरी के मालिक के 'अभिकर्ता' के रूप में वर्णित किया जा सकता है जिसमें 9 मार्च 2000 को या उसके आसपास एक दुर्भाग्यपूर्ण घातक घटना हुई थी। हमारी राय में, पहले प्रश्न का उत्तर सकारात्मक होना चाहिए, जबकि संबंधित प्रश्न का उत्तर नकारात्मक होना चाहिए।

तथ्य

7. 15 दिसंबर 1999 को खान सुरक्षा निदेशक, रांची क्षेत्र, रांची द्वारा खान अधिनियम, 1952 की धारा 22ए (2) (संक्षेप में अधिनियम)1 के तहत एक आदेश जारी किया गया था। विश्रामपुर और बुकबुका सीमों में समय दिए जाने के बावजूद कुछ दोषों को सुधारने में एजेंट, करकट कोलियरी की विफलता से संबंधित आदेश| तदनुसार, आदेश के आधार पर खानों के मुख्य निरीक्षक ने दोषों को ठीक होने तक बुकबुका सीम के विस्तारित ब्लॉक बी से कोयला निकालने के लिए व्यक्तियों के रोजगार पर प्रतिबंध लगा दिया।

---

1. 22-ए। कुछ मामलों में रोजगार को प्रतिबंधित करने की शक्ति।-(1) जहां सुरक्षा से संबंधित किसी मामले के संबंध में, जिसके लिए इस अधिनियम द्वारा या उसके तहत स्पष्ट प्रावधान किया गया है, किसी खदान का मालिक, एजेंट या प्रबंधक ऐसे प्रावधानों का पालन करने में विफल रहता है, तो मुख्य निरीक्षक लिखित रूप में नोटिस दे सकता है जिसमें उसे उस चूने के भीतर अनुपालन करने की आवश्यकता होती है जिसे वह नोटिस में निर्दिष्ट कर सकता है या चूने की ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर जो वह समय-समय पर, उसके बाद निर्दिष्ट कर सकता है।

(2) जहां मालिक, अभिकर्ता या प्रबंधक, यथास्थिति, ऐसी सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर या उस उप-धारा के तहत विनिर्दिष्ट विस्तारित अवधि के भीतर, उप-धारा (1) के तहत दी गई सूचना की शर्तों का पालन करने में विफल रहता है, तो मुख्य निरीक्षक, लिखित आदेश द्वारा, खदान में या उसके आसपास या उसके किसी हिस्से में किसी ऐसे व्यक्ति के नियोजन पर प्रतिबंध लगा सकता है, जिसका नियोजन, उसकी राय में, सूचना की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए यथोचित रूप से आवश्यक नहीं है।

(3) और (4) xxx.

8. निषेधात्मक आदेश के बावजूद, कोयला निष्कर्षण स्पष्ट रूप से करकट कोलियरी में किया गया था और 9 मार्च 2000 को या उसके आसपास एक दुर्भाग्यपूर्ण घातक दुर्घटना हुई थी। दुर्घटना के कारण और परिस्थितियों की जांच मार्च और अप्रैल 2000 में कई तारीखों पर खदानों के निरीक्षण द्वारा की गई थी।दुर्घटना स्थल की जांच और निरीक्षण से पता चला कि कर्काटा कोलियरी में बुकबुका सीम के ब्लॉक बी में निषेधात्मक आदेश का उल्लंघन करते हुए कोयला निकाला जा रहा था।

9. निषेधात्मक आदेश के उल्लंघन का सुझाव देने वाली जांच रिपोर्ट के परिणामस्वरूप, खान निरीक्षक ने 30 अगस्त 2000 को रांची में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष 2000 का मामला

संख्या 323 दायर किया। शिकायत दर्ज करने के लिए अग्रणी घटनाओं का उल्लेख किया गया था और यह आरोप लगाया गया था कि चूंकि निषेधात्मक आदेश के उल्लंघन में खनन कार्यों और कोयला उत्पादन के लिए व्यक्तियों की संलिप्तता के संकेत थे, इसलिए तीन आरोपी व्यक्ति, जी. एन. वर्मा जो मुख्य महाप्रबंधक (उत्तरी करणपुरा क्षेत्र) और डीम्ड एजेंट, करकट कोलियरी, बी. के. सिन्हा, एजेंट, करकट कोलियरी और बी. के. घोष, मैनेजर, करकट कोलियरी ने अधिनियम की धारा 72-8 के प्रावधानों का उल्लंघन किया था और उस धारा के प्रावधानों के तहत दंडित किए जाने के लिए उत्तरदायी थे।2

10. 31 अगस्त 2000 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने शिकायत का संज्ञान लिया और अपीलार्थी जी. एन. वर्मा सहित अभियुक्त व्यक्तियों को समन जारी किया।

72-बी| धारा 22 के तहत आदेशों के उल्लंघन के लिए विशेष प्रावधान। जो कोई भी धारा 22 की उप-धारा (1-ए), उप-धारा (2) या उप-धारा (3) के तहत या धारा 22-ए की उप-धारा (2) के तहत जारी किसी भी आदेश का उल्लंघन करते हुए खदान में काम करना जारी रखता है, वह दो साल तक की अवधि के कारावास से दंडनीय होगा, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा जो पांच हजार रुपये तक हो सकता है। बशर्ते कि न्यायालय के निर्णय में इसके विपरीत लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले विशेष और पर्याप्त कारणों के अभाव में, ऐसा जुर्माना दो हजार रुपये से कम नहीं होगा।

उच्च न्यायालय में कार्यवाही

11. समन प्राप्त होने पर, जी. एन. वर्मा ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के तहत एक याचिका दायर की जिसमें कार्यवाही और उन्हें जारी किए गए समन को रद्द करने की मांग की गई थी। जी. एन. वर्मा द्वारा दायर याचिका आपराधिक विविध 2000 आर की संख्या 8331 होने के कारण झारखंड उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा सुनवाई के लिए लिया गया था जिन्होंने नोट किया कि उनके सामने सवाल यह था कि क्या एक एजेंट के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को इस आधार पर अधिनियम के तहत अपराध के लिए आपराधिक दायित्व के साथ लगाया जा सकता है कि वह एक मानित एजेंट है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने *आर. जे. सिन्हा बनाम राज्य*3 में पटना उच्च न्यायालय की खंड पीठ के निर्णय को नोट किया और कहा कि अधिनियम में अभिकर्ता की परिभाषा में संशोधन किया गया था क्योंकि सिन्हा में दिए गए निर्णय और उप-धारा (5) को भी अधिनियम की धारा 18 में पेश किया गया था। तदनुसार, उनका विचार था कि अधिनियम की धारा 18 (5) के आयात पर आगे विचार करने की आवश्यकता है और इसलिए, मामले को आगे के विचार के लिए डिवीजन बेंच को भेज दिया गया है।

12. डिवीजन बेंच ने मामले को सुनवाई के लिए लिया और 19 सितंबर 2002 के अपने फैसले और आदेश द्वारा (विवादित) इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि 1983 में इसके संशोधन से पहले अधिनियम में एजेंट की परिभाषा को काफी व्यापक कर दिया गया था ताकि खदान के मालिक की ओर से कार्य करने वाले या कार्य करने का इरादा रखने वाले और किसी भी खदान या उसके किसी भी हिस्से के प्रबंधन, नियंत्रण, पर्यवेक्षण या निर्देश में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को शामिल किया जा सके। नतीजतन, सिन्हा में निर्धारित कानून अब लागू नहीं था।

13. अधिनियम की धारा 2 (सी) में इसके संशोधन से पहले और उसके बाद आने वाले एजेंट की परिभाषा इस प्रकार हैः

"2 (ग)" "अभिकर्ता" " का जब किसी खदान के संबंध में उपयोग किया जाता है, तो उसका अर्थ है कोई भी व्यक्ति, चाहे वह नियुक्त किया गया हो या नहीं, जो खदान या उसके किसी हिस्से के प्रबंधन, नियंत्रण और दिशा के संबंध में मालिक के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है और इस प्रकार इस अधिनियम के तहत प्रबंधक से वरिष्ठ है।"

इसके संशोधन के बाद, अधिनियम की धारा 2 (सी) इस प्रकार हैः

"2 (ग)" "अभिकर्ता" "का जब किसी खदान के संबंध में उपयोग किया जाता है, तो उसका अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह नियुक्त किया गया हो या नहीं, जो मालिक की ओर से कार्य करता है या कार्य करने का इरादा रखता है, खदान के किसी भी हिस्से के प्रबंधन, नियंत्रण, पर्यवेक्षण या निर्देशन में भाग लेता है।"

14. डिवीजन बेंच ने अधिनियम की धारा 18 में संशोधन और उसमें उप-धारा (5) को लागू करने पर भी विचार किया। यह उपखंड इस प्रकार हैः

"(5) किसी भी व्यक्ति द्वारा, किसी भी उल्लंघन की स्थिति में, जो इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए विनियमों, नियमों, उपनियमों या आदेशों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है, सिवाय उन लोगों के जो विशेष रूप से किसी व्यक्ति से कोई कार्य या चीज़ करने की अपेक्षा करते हैं या किसी व्यक्ति को कोई कार्य या चीज़ करने से रोकते हैं, उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के अलावा, निम्नलिखित व्यक्तियों में से प्रत्येक को भी इस तरह के उल्लंघन का दोषी माना जाएगा जब तक कि वह यह साबित न कर दे कि उसने प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित परिश्रम का उपयोग किया था और इस तरह के उल्लंघन को रोकने के लिए उचित साधन अपनाए थेः -

(i) उल्लंघन किए गए प्रावधानों के संबंध में पर्यवेक्षण के कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त अधिकारी;

(ii) खदान का प्रबंधक;

(iii) खदान का मालिक और अभिकर्ता;

(iv) उप-धारा (2) के तहत जिम्मेदारी निभाने के लिए नियुक्त व्यक्ति, यदि कोई हो;

बशर्ते कि उपरोक्त व्यक्तियों में से किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती है यदि यह जांच और जांच पर दिखाई देता है, कि वह *प्रथम दृष्टया उत्तरदायी* नहीं है|

15. उच्च न्यायालय की राय थी कि अधिनियम की धारा 18 (5) के साथ पठित अभिकर्ता की विस्तारित परिभाषा को देखते हुए, खदान का मुख्य महाप्रबंधक एक ऐसा अभिकर्ता माना जाएगा जो किसी खदान या उसके किसी हिस्से के प्रबंधन, नियंत्रण, पर्यवेक्षण या निर्देशन के लिए जिम्मेदार होगा। इस आधार पर यह अभिनिर्धारित किया गया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने जी. एन. वर्मा के खिलाफ शिकायत का उचित संज्ञान लिया और इसलिए कार्यवाही को रद्द करने के लिए उनके द्वारा दायर याचिका में कोई योग्यता नहीं थी।

16. यह ध्यान दिया जा सकता है कि न तो अभिकर्ता की परिभाषा और न ही अधिनियम की धारा 18 (5) किसी मानित अभिकर्ता को संदर्भित करती है। यह अभिव्यक्ति एक एजेंट की नियुक्ति से संबंधित कोयला खान विनियम, 1957 के विनियम 8-ए में पाई जाती है। विनियम 8-ए इस प्रकार हैः

"8-ए। अभिकर्ता की नियुक्ति

(1) खदान का मालिक मुख्य निरीक्षक और क्षेत्रीय निरीक्षक को लिखित रूप में एक बयान प्रस्तुत करेगा, जिसमें खदान के प्रबंधन, नियंत्रण, पर्यवेक्षण या निर्देश के संबंध में मालिक की ओर से कार्य करने के लिए अधिकृत प्रत्येक व्यक्ति का नाम और पदनाम दिखाया जाएगा।

(2) बयान में ऐसे प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारियों और उन मामलों को भी दर्शाया जाएगा जिनके संबंध में वह मालिक की ओर से कार्य करने के लिए अधिकृत है।

(3) ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को, यथास्थिति, ऐसे विवरण में निर्दिष्ट जिम्मेदारियों के संबंध में, खदान या खदानों के समूह का प्रतिनिधि माना जाएगा।

(4) उपरोक्त विवरण कोयला खान (संशोधन) विनियमन 1985 के लागू होने की तारीख से एक महीने के भीतर, पहले से खोली गई या पुनः खोली गई खानों के मामले में, और अन्य मामलों में खदान खुलने की तारीख से एक महीने के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा।

(5) उपरोक्त कथन के नामों या अन्य विवरणों में किसी भी परिवर्तन, जोड़ या परिवर्तन की सूचना मुख्य निरीक्षक और क्षेत्रीय निरीक्षक को परिवर्तन, जोड़ या परिवर्तन की तारीख से सात दिनों के भीतर लिखित रूप में दी जाएगी।

बहस

17. यह सच है कि अधिनियम में "अभिकर्ता" का एक विस्तारित अर्थ है। यह न केवल एक ऐसे व्यक्ति को अपने दायरे में लाता है जिसे खदान के संबंध में एक एजेंट के रूप में नियुक्त किया जाता है, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति को भी अपने दायरे में लाता है जिसे एजेंट के रूप में नियुक्त नहीं किया गया है, बल्कि जो खदान के मालिक की ओर से कार्य करता है या कार्य करने का इरादा रखता है और खदान या उसके किसी भी हिस्से के प्रबंधन, नियंत्रण, पर्यवेक्षण या निर्देशन में भाग लेता है।

18. यह किसी का मान्यता नहीं है कि जी. एन. वर्मा को किसी भी खदान का एजेंट नियुक्त किया गया था। इसके अलावा, शिकायत में कहीं भी यह आरोप या उल्लेख नहीं किया गया है कि जी. एन. वर्मा ने खदान के मालिक की ओर से काम किया या कथित रूप से काम किया या उन्होंने किसी भी खदान के प्रबंधन, नियंत्रण, पर्यवेक्षण या निर्देशन में भाग लिया। वास्तव में शिकायत में उनके कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का वर्णन नहीं किया गया है। शिकायत में जी. एन. वर्मा के कर्तव्यों का उल्लेख नहीं होने के कारण, यह कहना संभव नहीं है कि क्या वह करकट कोलियरी के मुख्य महाप्रबंधक होने के नाते केवल एक प्रशासनिक प्रमुख थे या उन्हें करकट कोलियरी में किसी भी खदान के प्रबंधन, नियंत्रण, पर्यवेक्षण या दिशा से संबंधित तकनीकी मुद्दों में शामिल होने की आवश्यकता थी। शिकायत में कथन नीरस और अस्पष्ट है और इसका प्रभाव यह है कि प्रासंगिक समय में जी. एन. वर्मा मुख्य महाप्रबंधक/मानित अभिकर्ता थे और खदान के पर्यवेक्षण, प्रबंधन और नियंत्रण का प्रयोग कर रहे थे और उस क्षमता में यह देखने के लिए बाध्य था कि सभी खनन कार्य अधिनियम, नियमों, विनियमों, उसके तहत बनाए गए आदेशों के अनुसार किए गए थे।

19. *राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड बनाम हरमीत सिंह पेंटल और अन्य*4 में परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 और 141 के संदर्भ में यह निर्धारित किया गया है कि धारा 141 एक दंडात्मक प्रावधान है जो एक प्रत्यावर्ती दायित्व पैदा करता है। यह इस प्रकार आयोजित किया गया थाः

पीठ ने कहा, "इसलिए, एक शिकायत में यह संक्षिप्त बयान देना पर्याप्त नहीं है कि निदेशक (एक आरोपी के रूप में प्रस्तुत) निदेशक की भूमिका के बिना कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए कंपनी का प्रभारी और जिम्मेदार है। लेकिन शिकायत में यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि प्रतिवादी 1 अपने व्यवसाय के संचालन के लिए अभियुक्त कंपनी का प्रभारी कैसे और किस तरह से था या उसके प्रति उत्तरदायी था। यह दंडात्मक कानूनों की सख्त व्याख्या के अनुरूप है, विशेष रूप से, जहां ऐसे कानून प्रत्यावर्ती दायित्व पैदा करते हैं।

इसके बाद यह निष्कर्ष निकाला गयाः

पीठ ने कहा, "शिकायतकर्ता की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वह शिकायत में कानून के तहत आवश्यक विशिष्ट कथन करे ताकि आरोपी को परोक्ष रूप से उत्तरदायी बनाया जा सके। आपराधिक दायित्व को मजबूत करने के लिए, ऐसा कोई अनुमान नहीं है कि प्रत्येक निदेशक लेनदेन के बारे में जानता है।

20. जहाँ तक आपराधिक शिकायत का संबंध है, इसमें जी. एन. वर्मा के खिलाफ कोई आरोप नहीं है। उनके बारे में एकमात्र कथन यह है कि वे खदान के मुख्य महाप्रबंधक/मानित अभिकर्ता थे और खदान के पर्यवेक्षण, प्रबंधन और नियंत्रण का प्रयोग कर रहे थे और उस क्षमता में यह देखने के लिए बाध्य थे कि सभी खनन कार्य अधिनियम, नियमों, विनियमों, आदेशों के अनुसार किए गए थे। इस तरह के एक सामान्य बयान के आधार पर, जिसमें कोई विशिष्ट या अन्यथा आरोप, नहीं है, यह मानना मुश्किल है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने शिकायत का उचित संज्ञान लिया और जी. एन. वर्मा को समन जारी किया। इस न्यायालय द्वारा हरमीत सिंह पेंटल (हालांकि एक अन्य संदर्भ में) में निर्धारित कानून पूरी तरह से लागू होगा। इन परिस्थितियों में, हमारी राय है कि इस मामले के तथ्यों पर और उनके खिलाफ दायर शिकायत में कोई आरोप नहीं होने के कारण जी. एन. वर्मा के खिलाफ कार्यवाही के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया है।

21. दूसरा सवाल यह रहेगा कि क्या जी. एन. वर्मा को खदान का एजेंट माना जा सकता है।

22. कोयला खान विनियमों के विनियम 8-ए में खदान के मालिक को खदान के प्रबंधन, नियंत्रण, पर्यवेक्षण या निर्देश के संबंध में मालिक की ओर से कार्य करने के लिए अधिकृत प्रत्येक व्यक्ति का नाम और पदनाम लिखित रूप में प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। अभिलेख पर यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि ऐसा कोई बयान खदान के मालिक द्वारा मुख्य निरीक्षक या अधिनियम के तहत नियुक्त क्षेत्रीय निरीक्षक को दिया गया था। केवल एक व्यक्ति जो मालिक की ओर से कार्य करने के लिए अधिकृत है या मालिक की ओर से कार्य करने का इरादा रखता है, उसे एजेंट माना जा सकता है। यदि कोई बयान नहीं दिया गया है या मालिक द्वारा कोई संकेत दिया गया है जो जी. एन. वर्मा को अपनी ओर से कार्य करने या कार्य करने के लिए सक्षम बनाता है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि वह खदान के लिए एक मानित एजेंट थे।

23. अधिनियम की धारा 2 (जे) में 'माइन' शब्द को परिभाषित किया गया है और इसमें खदान के संबंध में किसी भी प्रशासनिक कार्यों का कोई संदर्भ नहीं है, लेकिन केवल उससे संबंधित तकनीकी मामले हैं5। जी. एन. वर्मा कर्कटा कोलियरी के मुख्य महाप्रबंधक थे और यह मान लेना संभव नहीं है कि प्रशासनिक कर्तव्यों का पालन करने के अलावा, वह बुकबुका सीम वाली खदान से संबंधित तकनीकी मामलों में भी शामिल थे।

5. खंड 2.
परिभाषा "खदान" का अर्थ है कोई भी खुदाई जहां खनिजों की खोज या प्राप्ति के उद्देश्य से कोई कार्रवाई की गई है या की जा रही है, और इसमें शामिल हैं -

24. डब्ल्यू. एच. किंग बनाम भारत गणराज्य6 में संविधान पीठ के फैसले से शुरू होने वाले निर्णयों की एक श्रृंखला द्वारा कानून को अच्छी तरह से तय किया जाता है कि जब कोई क़ानून अपराध पैदा करता है और जुर्माना और कारावास का जुर्माना लगाता है, तो धारा के शब्दों को सख्ती से विषय के पक्ष में समझा जाना चाहिए।

इस दृष्टिकोण को पिछले साठ से अधिक वर्षों से इस न्यायालय द्वारा लगातार अपनाया गया है।

25. इस मामले के तथ्यों पर, हमें जी. एन. वर्मा को खदान में हुई चूक के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में शामिल करने के लिए कानून को अनुचित रूप से विस्तारण की आवश्यकता होगी, जिसके परिणामस्वरूप एक घातक दुर्घटना हुई। हमारा विचार है कि इन परिस्थितियों में जी. एन. वर्मा के खिलाफ अधिनियम की धारा 72-8 के तहत कार्यवाही करने का कोई आधार नहीं है।

निष्कर्ष

26. अपील की अनुमति दी जाती है, उच्च न्यायालय के फैसले और आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है और जी. एन. वर्मा के खिलाफ शिकायत को खारिज कर दिया जाता है।

आर पी अनुमति दी गयी

(i) सभी बोरिंग, बोर होल, तेल के कुएं और सहायक कच्चे कंडीशनिंग संयंत्र, जिसमें तेल क्षेत्रों के भीतर खनिज तेल ले जाने वाली पाइप भी शामिल है;

(ii) खदान में या उससे सटे और उससे संबंधित सभी शाफ्ट, चाहे वे डूबने के दौरान हों या नहीं;

(iii) संचालित होने के दौरान सभी स्तर और झुके हुए सतह;

(iv) सभी ओपेन कास्ट कार्य;

(v) खनिजों या अन्य वस्तुओं की खदान में लाने या हटाने या उससे कचरे को हटाने के लिए प्रदान किए गए सभी कन्वेयर या हवाई रोपवे;

(vi) किसी खदान में या उसके आस-पास या उससे संबंधित सभी स्तर, सतह , मशीनरी, कार्य, रेलवे, ट्रामवे और साइडिंग;

(vii) किसी खदान में या उसके आस-पास किए जा रहे सभी सुरक्षात्मक कार्य;

(viii) किसी खदान की सीमा के भीतर और उसी प्रबंधन के तहत स्थित सभी कार्यशालाएं और स्टोर और मुख्य रूप से उस खदान या उसी प्रबंधन के तहत कई खदानों से जुड़े उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं;

(ix) केवल या मुख्य रूप से एक ही प्रबंधन के तहत खदान या कई खदानों को काम करने के उद्देश्य से बिजली की आपूर्ति के लिए सभी बिजली स्टेशन, ट्रांसफॉर्मर सब-स्टेशन, कनवर्टर स्टेशन, रेक्टिफायर स्टेशन और संचायक भंडारण स्टेशन।

(x) उस समय के लिए कोई परिसर जिसका उपयोग किसी खदान में उपयोग के लिए या किसी खदान से कचरा जमा करने के लिए रेत या अन्य सामग्री जमा करने के लिए किया जा रहा है या जिसमें ऐसी रेत, अपशिष्ट या अन्य सामग्री के संबंध में कोई कार्य किया जा रहा है, जो विशेष रूप से खदान के मालिक द्वारा कब्जा किया गया है;

(xi) किसी खदान में या उसके आस-पास और उससे संबंधित कोई परिसर जिस पर खनिजों या कोक की बिक्री के लिए कोई सहायक प्रक्रिया, ड्रेसिंग या तैयारी की जा रही है;

6. 1952 एस सी आर 418

यह अनुवाद पीयूष आनन्द, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया है।